

झारखंड की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है : मोदी

एजेंसी, नई दिल्ली।



भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कागिस, झामुआ और राजद पर तीखा हमता किया और उन पर बड़ी-बड़ी बातें कहने और अपने बातों को पूरा करने में फिलहर रहने का आरोप लगाया।

झारखंड में भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा बूथ सरसे मजबूत कार्यक्रम को नमों एप के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने चाहिए की इस टिप्पणी के लिए भी आलोचना की कि उनकी पार्टी ने लोगों को ज़ृती गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड वन व खनिज संबंध से भरपूर क्षेत्र है समृद्धि के बावजूद यहाँ विकास का अभाव और बोंजारी चरम पर है। इसका सबसे बड़ा कारण ध्वनीचार व झारखंड की अमूल्य प्रकृतिक संपदा की

बेतहाश लूट है। उन्होंने कहा कि कागिस जहा-जहा सता में है, वहाँ के लोगों को ऐसे ही ताजा है। कागिस के रास्तीय अवश्य मल्लिकार्जुन खरों ने स्वयं ही स्वाक्षर किया कि उनकी पार्टी ने लोगों को ज़ृती गारंटी दी है। खरों ने कहा कि राज सरकार से सहयोग नहीं मिलने के बावजूद केंद्र सरकार अपने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ राज्य के विकास को संकलित हो गया है, इसका सबसे बड़ा कारण ये थे भी है कि जेएमएम, कागिस व अरजंडी ने

अग्निशमन सेवाओं के विस्तार के लिए

725.62 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी

एजेंसी, नई दिल्ली।



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर अध्यक्षता में सोमवार को एक उच्च स्तरीय समिति ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधिकारिकीय योजना के तहत छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए 725.62 करोड़ रुपये की तीन विशेषज्ञ सेवाओं को मंजूरी दी है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार समिति ने छत्तीसगढ़ के लिए 147.76 करोड़ रुपये, ओडिशा के लिए 201.10 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल के लिए 376.76 करोड़ रुपये के मंजूर किये हैं। उच्च स्तरीय समिति में केंद्रीय वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपायक्ष सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा प्रतिरोधी भारत के विनां को पूरा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने गृह

कर्मीर में कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर महबूबा ने अब्दुल्ला को लिखा पत्र

एजेंसी, श्रीनगर।



जम्मू-कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से पत्र लिखकर आग्रह किया कि वह पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्मचारियों की बर्खास्ती के मामलों का पुरुषालूकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिक्षा समिति गठित किया जाए।

मुश्किली सुनियोजन की अपेक्षा सोलाली सेवाओं से सम्मान द्वारा से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने 'एक्स' पर कहा कि उमरीद है कि उमर महबूबा इस परिवर्य के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।